

Regarding establishment of Integrated Manufacturing Cluster in Garhwa under Palamau Constituencies

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : माननीय सभापति महोदया, मैं आपका ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत गढ़वा जिले में भवनाथपुर में सेल की 1,160 हेक्टेयर जमीन है, जिस पर एनआईसीडीसी के द्वारा अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का झारखंड राज्य में इंटीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव है।

इस संबंध में एनआईसीडीसी के एमडी और सीईओ के द्वारा झारखंड सरकार को एक पत्र लिखा गया था और गढ़वा जिले के उपायुक्त से छः बिन्दुओं पर एक प्रतिवेदन की मांग की गई थी। उपायुक्त ने उन छः बिन्दुओं पर अपना प्रतिवेदन झारखंड सरकार को भेज दिया है। परंतु उसके बाद भी झारखंड सरकार उस प्रस्ताव को लेकर बैठी हुई है, क्योंकि झारखंड सरकार यह नहीं चाहती है कि भवनाथपुर प्रखंड के अंतर्गत आईएमसी की स्थापना हो सके। जबकि आपको ज्ञात होगा कि 112 आकांक्षी जिलों के तहत गढ़वा जिला भी आता है और निश्चित रूप से यहां पर विकास की ज्यादा आवश्यकता है।

महोदया, 1,160 हेक्टेयर जमीन का जो विषय है, उसके विरुद्ध केवल 760 हेक्टेयर जमीन बोकारो में उपलब्ध है। राज्य सरकार बोकारो में आईएमसी की स्थापना करना चाहती है। बोकारो पहले से ही इंडस्ट्रियल विकसित जिला है।

अतः मेरा आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि एनआईसीडीसी की एक टीम वहां पर भेजी जानी चाहिए और एक कंपैरेटिव इवैल्यूशन होना चाहिए कि आईएमसी की स्थापना भवनाथपुर प्रखंड के अंतर्गत ज्यादा जरूरी है या फिर बोकारो के अंतर्गत ज्यादा जरूरी है। अगर एक बार इवैल्यूशन रिपोर्ट आ जाएगी, तो फिर इसके औचित्य या अनौचित्य पर विचार किया जा सकेगा एवं उसके आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा।

महोदया, आपको पता है कि जो 112 आकांक्षी जिले हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि ये जिले विकसित हो सकें और मुख्य विकसित जिलों की श्रेणी में आ सकें। ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार के प्रस्ताव को निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलना चाहिए।